ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 98-99

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

ग्रामीण शक्ति संरचना का बदलता स्वरूप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. डॉ0 अर्चना श्रीवास्तव
2. डॉ0 राजीव कुमार श्रीवास्तव

1. असि0 प्रोफेसर– शिक्षा शास्त्र विभाग, सतीश चन्द्र कालेज, 2. असि0 प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, श्री सुदृष्टि बाबा पी०जी० कालेज, सुदिष्टपुरी– रानीगंज, बलिया (उ0प्र0), भारत

Received-27.07.2023, Revised-03.08.2023, Accepted-08.08.2023 E-mail: archanasri2610@gmail.com

सारांश: ***शक्ति संरचना तथा सामाजिक संरचना की बीच घनिष्ट सम्बंध है। शक्ति संरचना सामाजिक संरचना का एक आधार है, क्योंकि शक्ति को समझे बिना किसी भी समाज की संरचना को समझना सम्भव नहीं है। जिसके पास शक्ति होती है, वहीं समाज की संरचना का निर्णायक रूप देता है। आजादी के बाद, जागीरदारी और ग्रामीण संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों के बारे में मध्यक्षेत्रीय सामान्वीयकरण एक कठिन कार्य है। आजकल समूह और व्यक्ति दोनों प्रकार्यात्मक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। इसके नाते सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान भी बदल हैं। गाँवों में जाति आज भी सामाजिक स्तरीकरण की एक मुख्य इकाई है, परन्तु अन्य कारक भी विभेदीकरण लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। गाँवों में आजकल जाति के नाम से व्यक्ति को सामाजिक संस्तरण में स्थान नहीं मिल रहा है, बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति इसमें महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर शोध आलेख के विषय का चयन किया गया। आलेख का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज में शक्ति संरचना में हुए बदलाओं का पता लगाना है।***

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक संरचना, शक्ति संरचना, निर्णायक रूप, जागीरदारी, सामाजिक स्तरीकरण, मध्यक्षेत्रीय सामान्वीयकरण ।

डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है, जो प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह किसी भी जाति, धर्म लिंग या पहचान से रखता हो) को समूह या समाज के मामलों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। ग्रामीण समुदाय के लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में एकरूपता देखने को मिलती हैं। उनके व्यवसाय, भाषा, धर्म, रीति–रिवाज, आदर्श, संस्थाएं, आचार–विचार एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण सामान्यतः सामान्य होता है। उनके जीवन में नगरीय लोगों की तरह अनेक विभेद और विषमताएं नहीं पाई जाती हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नियोजित विकास योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों वैश्वीकरण एवं नगरीकरण ने ग्रामीण सामाजिक संरचना में व्यापक प्रभाव डाला है। ग्रामीण विकास नीतियों एवं योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र परिवहन सुविधाएँ, सूचना एवं जनसंचार के माध्यम शिक्षा स्वास्थ आदि की उपलब्धता बढ़ी है। जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय का बाहय जगत से सम्पर्क बढ़ा है। नवीन पंचायती राज व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हेतु किये गये प्रावधानों से वंचित वर्गो से राजनीतिक चेतना का संचार हुआ है। इससे ग्रामीण शक्ति संरचना में भी परिवर्तन आया है। विकास योजनाओं में ग्रामीण संस्थाओं के स्वरूपों में सार्थक परिवर्तन हुआ और भारतीय ग्रामीण की प्रमुख संस्थाएँ, परिवार, विवाह, जाति, जजमानी आदि के प्रतिमानों में परिवर्तन आया है। आधुनिक मूल्यों प्रथाओं संस्थाओं में परिवर्तन हुआ है।

सरकार द्वारा विकास योजनाओं को ग्रामीण समाज पर लागू करने से भारत के गाँव लगातार प्रगति के पथ अग्रसर हैं। वास्तव में, ग्रामों में जिस गति से विभिन्न तरह की सुविधाएं पहुँच रही है। उसी तरह से लोगों के रहन–सहन और कार्य की प्रणाली में बदलाव भी आ रहा है। ग्रामीण विकास योजनाओं का स्पष्ट प्रभाव गाँवों की सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर रखा जा सकता है। सामाजिक संरचना की मुख्य पक्ष –जाति, सम्प्रदाय अथवा धार्मिक समुदाय और परिवार तथा रिश्तेदारों समूह अकेले पृथक–पृथक रहकर कार्य नहीं कर सकती हैं। एक दूसरे का सहयोग ग्राम संघर्ष का भी रंगमंच है। संघर्ष समझौता और सामाजिक एकजुटता के उसके अपने रूढ़िवादी तरीके हैं। दूसरी ओर विभिन्न ग्रामों में अधिक गुटबंदी और बराबर चलते रहने वाले संघर्ष उनकी विशेषताएँ हैं। विकास का पक्ष माने जाने वाले गाँव में यथार्थ में विभिन्न औपचारिक तथ्य कानूनी संस्थाएँ हैं। विभिन्न ग्रामों में राजनीतिक पार्टियों के अपने कार्यकर्ता हैं और बड़ें ग्रामों में उनके राजनीतिक पार्टियों का कार्यालय है। गाँव की अपनी एक अलग पहचान है, सुनिर्धारित क्षेत्र हैं, गाँव की सामान्य सम्पत्ति तथा साझा संसाधन जैसे कुएँ – तालाब आदि होते हैं। वहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा गुरुद्वारा हो सकता है। धार्मिक स्थलों में सभी लोगों का प्रवेश रहता है या यह भी हो सकता है कि केवल धर्म विशेष को अपनाने वाले लोगों के लिए दरवाजा खुला हो।

1. डॉ. सिंह, योगेन्द्र ने अपनी पुस्तक लिखा है कि परम्परागत ग्रामीण भारत मे शक्ति–संरचना के तीन आधार थे– जमींदारी प्रथा, ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत ।[1]

2. डॉ. सिंह, बैजनाथ ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि ग्रामीण नेतृत्व की यह विविधता मूल रूप से विभिन्न विकास योजनाओं तथा सामाजिक जागरूकता का परिणाम है।[2]

3. डॉ. मोदी, अनीता (2014) का कहना है कि ''पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रावधन होने से महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस आरक्षण व्यवस्था के कारण ही महिलाएँ अपने घर की देहरी से बाहर कदम रखकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए, अपनी क्षमता और कौशल का परिचय दे रही हैं।[3]

अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुलांक 38 प्रतिशत राजनीतिक और 34 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है।

निष्कर्ष– स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में औद्योगीकरण, यंत्रीकरण की प्रक्रिया की तीव्र गतिशीलता का रूप देखने को मिला है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने तरह–तरह के ग्रामीण – योजनाओं के माध्यम से सम्पूर्ण आर्थिक–सामाजिक एवं

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

सांस्कृतिक ढाँचें में बदलाव लाने का प्रयास किया है। यातायात साधनों और संचार के साधनों की प्रगति ने शहर और गाँव को परस्पर जोड़ा है। वैज्ञानिक कृषि के साधनों ने कृषि व्यवसाय को आधुनिक बनाया है। कृषि व्यवसाय का आधुनिकीकरण होने से ग्रामीण समाज की जीवन में आमूल–चूल परिवर्तन आया है।[5] ग्रामीण आर्थिक संरचना में बदलाव हो रहे हैं। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और कई भूमि सुधार पेश किए गए। जिन्होंने पारंपरिक शक्ति संरचना को कमजोर कर दिया और एक नई शक्ति संरचना का निर्माण किया । वंशानुगत और जाति के नेताओं के स्थान पर, राजनीतिक समर्थन वाले निर्वाचित व्यक्ति नेता बन गए। व्यक्तिगत योग्यता न कि जाति या वर्ग नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। गाँवों के वे लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति को खेती, रोजगार, शिक्षा आदि के माध्यम से अच्छा बना लिये है और जिनका बाह्य जगत से सम्पर्क बढ़ गया है। ऐसे लोगों की सामाजिक परिस्थिति बदली है और सामाजिक स्तरीकरण में इनके वर्ग की स्थिति उँची हुई है, भले ही जाति की स्थिति यथावत हो। ये परिवर्तन प्रगति और आधुनिक समाज के द्योतक हैं। स्पष्ट है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में प्रतिशत राजनीतिक और समाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Singh,yogendra "The changing power structure of village community: A case study of a villages in Eastern up, Rural sociology in India (ed) AR Desai. Pp. 711 & 723.
2. Singh, B.N "The important of community development programme on rural leadership" in leadership and political institution in India (ed) L. Park and tinker, pp. 358 & 371.
3. आहूजा, राम, ''भारतीय समाजशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली और जयपुर।
4. एस. सी. दूबे, ''भारतीय समाज'' नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 2002 1 गुप्ता, एम.एल एवं शर्मा, डी.डी. ''भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2010.
5. सिंह, जे. पी. ''आधुनिक भारत का समाज'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2019 सचदेव, डी. आर., ''भारत में समाज कल्याण प्रशासन'', किताब महल, 22 ए सरोजिनी प्रयागराज 2005 नायडू मार्ग।

*****